भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4037
जिसका उत्तर मंगलवार 20 मार्च, 2018 को दिया जाना है

विद्युत चालित वाहनों को चार्ज करने संबंधी अवसंरचना

4037. श्री बी विनोद कुमार:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्ष 2030 तक देश में केवल विद्युत चालित वाहन (ईवी) बेचने का लक्ष्य बना रही है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त वाहनों हेतु सम्पूर्ण देश में एक मजबूत चार्ज करने संबंधी अवसंरचना की आवश्यकता है; और

(ग) सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में चार्जिंग नेटवर्क की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग): वर्तमान में, भारी उद्योग विभाग के पास वर्ष 2030 तक देश में बेचे जाने वाले केवल इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवीज) के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, यह देखा गया है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए एक मजबूत चार्जिंग अवसंरचना की आवश्यकता होगी।

चार्जिंग अवसंरचना विकसित करने के लिए, विभिन्न बल दिए जाने वाले क्षेत्रों नामतः प्रायोगिक योजना, प्रौद्योगिकी विकास और चार्जिंग अवसंरचना के तहत प्राप्त विशिष्ट परियोजनाओं पर फेम इंडिया स्कीम [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का विनिर्माण और तीव्र अंगीकरण] के चरण एक के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु विचार किया गया।

******